भारत सरकार

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

****

मासिक मंत्रिमंडल सारांश दिसम्बर-2020

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:

(i) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति

देश में पूरे बायोटेक क्षेत्र के लिए लक्ष्यों की संकल्पना के लिए चाहे वह शिक्षा हो, अनुसंधान हो, उद्यमिता हो, उद्योग विकास हो, प्रख्यात विशेषज्ञों की मदद से लक्ष्यों और कार्यान्वयन योजना के साथ 5 साल की रणनीति का मसौदा किया जा रहा है।

एनबीडीएस 2021-25 के प्रारूपण के लिए, एक समिति का गठन किया गया था, अब तक 2 बैठकें आयोजित की गई थी और अंतिम मसौदे को मंजूरी के लिए तैयार किया जा रहा है।

(ii) कोविड-19 से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए डीबीटी द्वारा किए गए उपाय

क. मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन

"मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन" का प्रस्ताव डीबीटी के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बीआईआरएसी, द्वारा 12 माह के लिए 900 करोड़ रूपये की कुल लागत पर कार्यान्वित किया जाना था, का माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। अनुदान की पहली किश्त जारी होने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, कोविड-19 वैक्सीन विकास और पारिस्थितिकी तंत्र सहयोगी रुचियों में अभिव्यक्ति दर्शाने के लिए (तीन अनुरोध) डीबीटी-बीआईआरएसी द्वारा भी जारी किए गए हैं जिनमें (1) कोविड-19 वैक्सीन कैंडीडेट का विकास, (2) कोविड-19 वैक्सीन विकास के समर्थन के लिए क्षमता में वृद्धि और (3) कोविड-19 वैक्सीन कैंडीडेट के लिए मानव नैदानिक परीक्षण के संचालन की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन 18 दिसम्बर, 2020 और 23 दिसम्बर, 2020 को आयोजित वैज्ञानिक सलाहकार समूह (एसएजी) की बैठकों में किया गया था।

ख. नैदानिक परीक्षण पहल में तेजी लाने के लिए भागीदारी (पीएसीटी)

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने नैदानिक परीक्षण पहल के लिए भागीदारी (पीएसीटी) शुरू की है। पीएसीटी कार्यक्रम के तहत, डीबीटी पड़ोसी/मित्र राष्ट्रों में कोविड वैक्सीन के चरण III नैदानिक परीक्षणों की सुविधा की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस पहल के तहत, निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैं:

- इंडो-सीईपीआई मिशन के तत्वावधान में पड़ोसी देशों में नैदानिक परीक्षण अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण।
- भारतीय कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण पड़ोसी और मित्र देशों में सुविधा मुहैया कराना।

नैदानिक परीक्षण पहल में तेजी लाने के लिए साझेदारी (पीएसीटी) के 'पड़ोसी देशों में नैदानिक अनुसंधान क्षमता मजबूत करने के लिए 4 मॉड्यूल, प्रशिक्षण' के तहत 11 दिसंबर, 2020 को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, श्रीलंका के 44 प्रतिभागियों के साथ एक्जिट परीक्षा सहित संपन्न हुआ। ये प्रशिक्षण जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) और नैदानिक विकास सेवा एजेंसी (सीडीएसए) द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।

डीबीटी-बीआईआरएसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने 9 दिसंबर, 2020 को भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद में कोविड-19 वैक्सीन विकास में शामिल प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों के अध्यक्षों के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ समन्वय किया। वैक्सीन उत्पादन और मौजूदा नैदानिक परीक्षणों सहित फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान और विकास सुविधाओं, विनिर्माण क्षमता, विदेशी सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया।

ग. टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई)

डीबीटी ने 10 दिसंबर 2020 को आयोजित 15 वीं एनटीएजीआई बैठक में भाग लिया, जिसमें कुष्ठ रोग वैक्सीन की अंत: परिवर्तनशीलता, जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन की पहल, रोटावायरस वैक्सीन की कार्यान्वयन रिपोर्ट और कोविड-19 वैक्सीन के प्रयासों के मामलों पर चर्चा की गई। विभाग ने 8 और 16 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की कोविड-19 वर्किंग ग्रुप की 11 वीं और 12 वीं बैठक में भी भाग लिया, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग विकल्पों और कोविड -19 रोग के परिणाम और कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग के जरिये अंतर्विरोध पर चर्चा की गई।

घ. एसीटी त्वरक (एसीटी-ए) सुविधा परिषद

डीबीटी ने एसीटी त्वरक (एसीटी-ए) सुविधा परिषद (एफसी) की तीसरी बैठक में भाग लिया, जो 14 दिसम्बर, 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें एसीटी-ए के तहत गतिविधियों के प्राथमिकताकरण और संकटपूर्ण अंतराल वित्तपोषण के समाधान के लिए वित्तपोषण ढांचे पर चर्चा की गई।

ङ. भारत-अमेरिका वैक्सीन कार्यक्रम का संयुक्त कार्यकारी समूह

भारत-अमेरिका वैक्सीन कार्रवाई कार्यक्रम (वीएपी) के संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की एक व्यावसायिक बैठक, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान (एनआईएआईडी), का एक द्विपक्षीय कार्यक्रम; 15 दिसंबर, 2020 को आयोजित किया गया था। बैठक में वीएपी के तत्वावधान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न द्विपक्षीय पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन विकास प्रयासों पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया।

च. देश भर के सरकारी संस्थानों में कोविड-19 नमूनों का परीक्षण में वृद्धि के लिए हब और स्पोक मॉडल में शहरी/क्षेत्रीय समूह स्थापित किए गए है। ये हब

आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों (डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, आईसीएआर आदि) द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाएँ हैं। अब तक 21 शहरी/क्षेत्रीय समूहों की स्थापना की गई हैं और 23.51 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।

ग्रामीण भारत में परीक्षण की पहुंच को और अधिक सक्षम बनाने के लिए, माननीय मंत्री द्वारा कोविड परीक्षण के लिए 18 जून, 2020 को शुरू की गई आई-लैब (संक्रामक रोग प्रयोगशाला) ने फरीदाबाद क्षेत्र में लगभग 10025 परीक्षण किए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से तीन और प्रयोगशालाओं की स्थापना की उम्मीद है। डीबीटी ने परीक्षण जारी रखने के लिए सभी केंद्रों को जनशक्ति सहायता प्रदान की है।

(iii) किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में आरएफपी पर आधारित नई परियोजनाएँ

क. डीबीटी और बीआईआरएसी ने प्रस्तावों कोविड-19 अनुसंधान संघ के लिए एक संयुक्त आमंत्रण की घोषणा की शिक्षाविदों से निदान से संबंधित प्राप्त कुल 120 प्रस्तावों की समीक्षा की गई, समर्पित क्षेत्र समीक्षा पैनलों (एआरपी) की बैठकों के माध्यम से समर्थन के लिए 17 अनुशंसित प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए संसाधित किया जा रहा है। नैदानिक विकास पर 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

ख. भारत-स्वीडन संयुक्त उद्यम समीक्षा द्वारा 'भारत और स्वीडन में स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कृत्रिम बौद्धिकता' पर एक संयुक्त कॉल के तहत छह प्रस्तावों की सिफारिश की गई है।

(iv) डीबीटी की सामाजिक पहुंच

क. फर्स्ट हब: स्टार्ट-अप और नवोन्मेषकों के लिए नवाचार और विनियमों की सुविधा

डीबीटी द्वारा बीआईआरएसी में नवोन्मेषकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सुविधा इकाई फर्स्ट हब की स्थापना की गई है। दुनिया भर में मौजूदा स्थिति के संबंध में, नवोन्मेषकों के प्रश्नों को समाधान करने के लिए हर शुक्रवार को विशेष फर्स्ट हब कोविड-19 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दिसंबर माह में, कोविड-19 सत्र 11 दिसंबर, 2020 को आयोजित किया गया और इसमें 7 से अधिक प्रश्नों को स्पष्ट किया गया। सीडीएससीओ, आईसीएमआर, एनआईबी, जीईएम, केआईएचटी, बीआईएस, डीबीटी और बीआईआरएसी के प्रतिनिधि नियमन पाथवे, वित्तपोषण अवसर, सार्वजनिक उपलब्धि, आईवीडी परीक्षण और सत्यापन, मानक और विनिर्देशों, विनिर्माण और परीक्षण बुनियादी ढांचे के समर्थन पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौजूद थे।

ख. कोविड के लिए भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित आईवीडी के बारे में ई-ब्रोशर/कैटलॉग का संकलन किया गया है और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश कोविड निदान के लिए अभिकर्मकों और किट के निर्यात के लिए डीबीटी के संपर्क में हैं।

ग. डीबीटी के स्वायत्तशासी संस्थानों ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 (आईआईएसएफ-2020) समारोह के उद्घाटन के तौर पर 'विज्ञानयात्रा' का आयोजन किया।

(v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क. न्यूटन-भाभा पीएचडी प्लेसमेंट कार्यक्रम 2020-21 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा और संक्षिप्त सूची बनाने के लिए 8 दिसंबर 2020 को विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोजित की गई। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों की उम्मीदवारों के बारे में ब्रिटिश काउंसिल के साथ 14 दिसंबर 2020 की अंतिम सूची के लिए संयुक्त पैनल की बैठक में चर्चा की गई। चयनित भारतीय अनुसंधान शोधकर्ताओं को यूके विश्वविद्यालय/संस्थान में 2-4 महीने के लिए अनुसंधान करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

ख. डॉ. रेणुस्वरुप, सचिव डीबीटी और प्रो. डेम ओटोलीनलेयर, मुख्य कार्यकारी, यूके अनुसंधान और नवाचार (यूकेआरआई); और प्रो. मेलानी वेलहम, एक्जीक्यूटिव, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेज रिसर्च काउंसिल (बीबीएसआरसी), ब्रिटेन के बीच 15 दिसंबर 2020 को एक आभासी बैठक हुई; वर्तमान वित्त पोषण परिदृश्य और द्विपक्षीय साझेदारी के भावी के अवसरों पर इस बैठक में चर्चा की गई।

ग. बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) और सेंटर नेशनल डी ला रिसर्च सांइटिफिक (सीएनआरएस) के बीच अनुसंधान सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के लिए अनुमोदित किया गया है।

(vi) प्रकाशन और पेटेंट

विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा 2 अनुसंधान प्रकाशन और 3 पेटेंट दायर किए गए हैं।

(vii) डीबीटी द्वारा समर्थित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और डीबीटी के स्वायत्तशासी संस्थानों के माध्यम से विकसित/वाणिज्यिकृत तकनीक: 1

क. बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) ने एक मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी ईटीयूआरएनएएल - एक इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक पेशेंट टर्निंग सिस्टम के लिए, जो स्टार्ट-अप कंपनी मैसर्स के क्यूरियस प्रा.लि. बैंगलुरू को लाईसेंस दिया है जिसे स्कूल ऑफ बायोडिजाइन (एसआईबी) कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई है।

II. महत्वपूर्ण मामलों/मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट

(i) लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण महत्वपूर्ण नीतिगत मामले : लागू नहीं

(ii) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति के निर्णयों का अनुपालन : लागू नहीं

अनुपालन के लिए लंबित सीओएस निर्णयों की संख्या	सीओएस निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा	टिप्पणियां
-	-	-

(iii) तीन माह से अधिक अवधि तक लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' के मामलों की संख्या- शून्य

(iv) ऐसे मामलों का विवरण जिसमें कार्य के आदान-प्रदान में परिवर्तन हुआ है : शून्य

(v) ई. गवर्नेंस कर्यान्वयन की स्थिति:

सक्रिय फाइलों की सं. 11,752	दिसम्बर, 2020 के दौरान सृजित ई-फाइलों की संख्या: 407

(vi) लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या: **31**	माह के अंत तक लम्बित लोक शिकायतों की संख्या: **37**

(vii) संचालन और विकास में तकनीक आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए कदम: शून्य

(viii) **क.** इस बात की पुष्टि करें कि मंत्रालय/विभाग और उसके संगठनों के एसीसी के दायरे में आने वाले सभी पदों के कार्यकाल का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है: यह पुष्टि की जाती है कि मंत्रालय/विभाग (डीबीटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्तशासी संस्थानों और उपक्रमों दोनों) में सभी पदों का विवरण एबीसी के दायरे में आने वाले एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है।

ख. एसीसी के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्थिति उन मामलों के संबंध में एक पैरा जिनमें अलग-अलग शीर्षकों में एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया हैं: यह पुष्टि की जाती है कि एसीसी के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

ग. उन मामलों की स्थिति, जहां पीईएसबी से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी एसीसी सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने हैं: सूचित किया जाता है कि इसे 'शून्य' समझा जाए।

(ix) सरकारी ई-बाज़ार (जीईएम) की स्थिति:

दिसंबर, 2020 **के महीने के लिए जीईएम के माध्यम से विभाग द्वारा की गई खरीद** 8,61,764.00 **रुपए है।**